



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2020 ई० (ज्येष्ठ 30, 1942 शक सम्वत्) [संख्या-20

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु० 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	323-336	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	259-304	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स, पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 328/XXXI(1)/2020-पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतन-लेवल 11 (वेतनमान ₹ 67,700-2,09,200) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री रावेन्द्र कुमार चौहान (दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत चलन क्रिया में)
- (2) श्री रतन लाल
- (3) श्री सत्येन्द्र वर्मन
- (4) श्रीमती सोनिया मनराल
- (5) श्रीमती विमला धपवाल
- (6) श्री गोकर्ण सिंह रावत

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका: 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

तकनीकी शिक्षा विभाग

विज्ञप्ति

12 मई, 2020 ई0

संख्या 318/XLI-A/2020-100/2017-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रेणी "क" के निम्नलिखित कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56(क) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगे/हो चुके हैं :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	संस्था का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्रीमती संगीता वर्मानी	प्रवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स	राजकीय पॉलिटेक्निक, आमवाला, देहरादून	07-02-1960	29-02-2020
2.	श्री वाचस्पति जमलोकी	विभागाध्यक्ष, सिविल	राजकीय पॉलिटेक्निक, कुलसारी, चमोली	08-02-1960	29-02-2020

3.	श्री हरिकान्त जोशी	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	राजकीय पॉलिटैक्निक, उत्तरकाशी	30-03-1980	31-03-2020
4.	श्री जगदीश चन्द्र पाठक	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	राजकीय पॉलिटैक्निक, चौनलिया, अल्मोड़ा	07-06-1980	30-06-2020
5.	श्री सुनील कुमार	उप निदेशक/ विभागाध्यक्ष बेसिक साइंस	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर गढ़वाल	02-09-1980	30-09-2020

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी अनुभाग

कार्यालय आदेश

19 मई, 2020 ई०

संख्या 206/XXIII/2020/01(03)/2020-शासन के कार्यालय आदेश संख्या 35/XXIII/2019/01(03)/2014 दिनांक 16-01-2019 के द्वारा कतिपय सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों को उप आबकारी आयुक्त वेतनमान ₹ 67700-208700 पे मैट्रिक्स लेवल-11 में पदोन्नत किया गया था।

2. उक्त आदेश दिनांक 16-01-2019 के क्रमांक-01 पर अंकित कार्मिक श्री तपन कुमार पाण्डेय के पदोन्नति FORGO (त्याग) करने विषयक पत्र दिनांक 17-01-2019 द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार किये जाने के दृष्टिगत श्री पाण्डेय की उप आबकारी आयुक्त के पद पर की गयी पदोन्नति निरस्त की जाती है।

कार्यालय आदेश दिनांक 16-01-2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

आबकारी विभाग

कार्यालय आदेश/पदोन्नति

20 मई, 2020 ई०

संख्या 225/XXIII/2020/01(05)/2019-तात्कालिक प्रभाव से निम्न आबकारी निरीक्षकों को सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स लेवल-10 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) सुश्री प्रतिमा गुप्ता
- (2) श्री गोविन्द सिंह मेहता

2. उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप उनके पदोन्नत पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को संपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. उक्त अधिकारियों की पदस्थापना/तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

15 मई, 2020 ई०

संख्या 752/XL-1/2020-26/2020-

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- आयुर्वेद/होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-19 महामारी के समय रोग प्रतिरोध क्षमता विकास हेतु कार्य योजना, 2020 (आयुष रक्षा कार्यक्रम) के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-S.16030/18/2009-NAM दिनांक 06 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या-L.11011/8/2020AS दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर्वेद एवं होम्योपैथ पद्धति से उपचार कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में राज्य के रैड एवं ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में निवासरत एवं क्वारेंटाइन केन्द्रों में रखे गये 5.00 लाख तथा कोविड वरियर्स पुलिस, चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं अन्य 50,000 हजार सहित कुल 5.50 लाख व्यक्तियों को निम्न Arsenicum album-30 एवं गिलोय+वासा+त्रिकटु+ तुलसी+मधुयष्टी का क्वाथ काढ़ा, संशमनी वटी, अश्वगंधा वटी इत्यादि औषधियों का क्य करते हुए निःशुल्क वितरण किया जाना है।

2- अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेद/होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-19 महामारी के समय रोग प्रतिरोध क्षमता विकास हेतु कार्य योजना, 2020 (आयुष रक्षा कार्यक्रम) निम्नवत प्रख्यापित की जा रही है।

कार्य योजना-

प्रस्ताव	क्रियान्वन
ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु राज्य स्तरीय आरोग्य कोविड सेल की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> ● निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं ● कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ● प्रोग्राम मैनेजर, राज्य आयुष मिशन, उत्तराखण्ड ● राज्य नोडल अधिकारी (आयुर्वेद), कोविड ● अन्य निदेशक व कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिकारी उक्त सेल में सदस्य रहेंगे

ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु जिलास्तरीय आरोग्य कोविड सेल की स्थापना	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी व उक्त के द्वारा नामित 1 चिकित्साधिकारी, 1 फार्मासिस्ट, 1 कार्यालय स्टाफसेल के सदस्य रहेंगे।
राज्य स्तरीय टेली परामर्श हेल्पलाइन नंबर	<ul style="list-style-type: none"> निदेशालय स्तरीय समस्त संयुक्त निदेशक/चिकित्साधिकारी कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विद्यालय द्वारा नामित 5 परामर्शदाता
जनपद स्तरीय टेली परामर्श हेल्पलाइन नंबर	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी व उनके द्वारा नामित जनपद के 2 चिकित्साधिकारी (1 महिला, 1 पुरुष)
आरोग्य केंद्रों की स्थापना	राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के परिसरों व सम्बद्ध निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिसरों को आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित करना व उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाना।

उपचार का विवरण:-

लक्ष्य	उपचार	उपचार का आधार	बजट हेतु प्राविधान का स्रोत	अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5
प्रथम चरण में रेड एवं ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में निवासरत एवं क्वारैंटाइन केंद्रों में रखे गये लगभग व्यक्ति 5.00 लाख तथा कोविड वरियर्स पुलिस, चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं अन्य 50,000	होम्योपैथिक पद्धति के अन्तर्गत: औषधि Arsenicum album-30 का व्यय विवरण प्रति व्यक्ति रू0 3.15 पैसे।	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने हेतु	होम्योपैथिक का अनुमानित व्यय:- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रू0 81,00,000 का बजट प्राविधान है।	—

लक्ष्य	उपचार	उपचार का आधार	बजट हेतु प्राविधान का स्रोत	अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5
प्रथम चरण में रैड एवं ऑरेंज जोन के अन्तर्गत चिह्नित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में निवासरत एवं क्वारेंटाइन केन्द्रों में रखे गये लगभग व्यक्ति 5.00 लाख एवं पुलिस चिकित्सक, ए.एन.एम.एवं पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य स्टाफ—50,000 हजार।	आयुर्वेद पद्धति के अन्तर्गत 1. गिलोय + वासा + त्रिकटु + तुलसी + मधुयष्टी का क्वाथ काढ़ा। 2. संशमनी वटी, 3. अश्वगंधा वटी उक्त औषधियों का 15 दिनों का व्यय रु० 86.00 एवं प्रत्येक किट एवं एडवाईजरी हेतु प्रिंटिंग इत्यादि पर होने वाला व्यय रु० 0.50 पैसे मात्र सहित कुल रु० 86.50 पैसे।	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने हेतु	आयुर्वेदिक का अनुमानित व्यय— 1. आयुष मिशन भारत सरकार से वर्ष 2019-20 में उपलब्ध धनराशि रु० 37.00 लाख। 2. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रु० 1.90 करोड़। आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत औषधियों का 15 दिनों का व्यय रु० 86.50 की दर से रु० 4,75,75,000 (चार करोड़ पच्चीस हजार मात्र) का अनुमानित व्यय प्राविधानित धनराशि रु० 2,27,00,000 (दो करोड़ सत्ताईस लाख) कम करते हुए रु० 2,48,75,000 (दो करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार) की धनराशि की आवश्यकता है। 3. मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से। 4. राज्य में स्थापित उद्योगों/कम्पनियों से सी०एस०आर० के अन्तर्गत सहयोग।	रु० 2.48 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) की धनराशि की आवश्यकता है।
योग—5.50 लाख				

कोविड वारियर्स (चिकित्सा कर्मी, पुलिस इत्यादि) का आयुर्वेदिक चिकित्सा व योग के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु लगभग 50,000 व्यक्ति।	<p>1. होम्योपैथिक पद्धति के अन्तर्गत— औषधि Arsenicum album-30 का व्यय विवरण प्रति व्यक्ति रु० 3.15 पैसे।</p> <p>1. आयुर्वेद पद्धति के अन्तर्गत गिलोय+वासा+त्रिकटु+ तुलसी+मधुयष्टी का क्वाथ काढ़ा। संशमनी वटी, अश्वगंधा वटी उक्त औषधियों का 15 दिनों का व्यय रु० 86.00 एवं प्रत्येक किट एवं एडवाईजरी हेतु प्रिंटिंग इत्यादि पर होने वाला व्यय रु० 0.50 पैसे मात्र सहित कुल रु० 86.50 पैसे।</p> <p>नस्य सरसो अथवा अणु तेल (उपलब्धता के अनुसार)</p>
कुल व्यक्ति 5,50,000	अतिरिक्त धनराशि की मांग रु० 2.48 लाख

होम्योपैथिक विभाग — कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-S16030/18/2019-NAM दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा कोरोना संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों को प्रिवेंशन (Prophylactic) के रूप में होम्योपैथिक औषधि **Arsenicum album-30** का सेवन किये जाने की सलाह दी गयी है, **Arsenicum album-30** के सेवन से व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु वर्तमान समय में प्रदेश में स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र के औषधि विक्रेताओं के पास होम्योपैथिक औषधि **Arsenicum album-30** का पर्याप्त मात्रा में भण्डार उपलब्ध है, जिससे प्रथम चरण में कोविड-19 संक्रमण हेतु सरकार द्वारा राज्य के घोषित रेडजोन एवं ऑरेंज ज़ोन के अन्तर्गत चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में निवासरत एवं क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गये व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार औषधियों के क्रय हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी :-

क्र. सं.	लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की लगभग संख्या	औषधि/औषधि वितरण से सम्बन्धित सामग्री का नाम	कुल मात्रा	औषधि क्रय हेतु अनुमानित धनराशि	कुल धनराशि का प्रति व्यक्ति व्यय
01	5,50,000	Arsenicum album-30 (100 ML)	2750 शीशी	17,32,500	3.15
02		प्लास्टिक फाइल्स (1 ड्राम)	5,50,000 पैकेट		
03		ग्लूबल्स 30 (नम्बर 450 ग्राम पैकिंग में)	5,50,000 पैकेट		
04		लिफाफे	5,50,000 पैकेट		
		योग		17,32,500	3.15

औषधि की उपलब्धता-

उपरोक्त वर्णित सभी आयुर्वेदिक औषधियां अत्यंत सुलभ हैं। उपरोक्त औषधियों में से पूर्वनिर्मित औषधियों का राज्य औषधि निर्माणशाला से अधिग्रहण कर आवश्यकतानुसार शेष औषधियों को प्राथमिकता के साथ सप्ताहभर में निर्माण हेतु निर्देशित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थापित 150 से अधिक निजी औषधि निर्माणशालाओं में से श्रेष्ठ औषधि निर्माणशालाओं का चयन कर उनको CSR (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत उपरोक्त में से पूर्वनिर्मित औषधियों को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु व अधिक आवश्यकता होने पर श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त उक्त औषधियों को राज्य निर्धारित दरों पर निर्माण किये जाने हेतु आग्रह किया जा सकता है।

जनसंख्या लक्ष्य -

प्रथम फेज के रूप में रेड ओर ऑरेंज कैटेगरी जनपदों में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में निवासरत एवं क्वारंटाइन केन्द्रों में रखे गये लगभग व्यक्ति-5.00 लाख एवं पुलिस, चिकित्सक, ए.एन.एम. एवं पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ-50,000 हजार सहित कुल 5.50 लाख व्यक्ति हैं। उक्त प्रस्ताव के अनुसार आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधीय वितरण किये जाने हेतु चुना जा सकता है। उक्त जनपदों में कार्य योजना के अनुसार सभी वर्गों के व्यक्तियों को विभिन्न माध्यमों से आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक औषधियां व चिकित्सात्मक औषधियां प्रदान की जा सकती हैं।

औषधि वितरण व्यवस्था-

राज्य में स्थित 750 से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/आयुष विंग्स व उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों व सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों/ चिकित्सालयों को आरोग्य केन्द्र के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित विभिन्न निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों को भी आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड के अंतर्गत 1300 चिकित्सा कर्मियों (चिकित्सक, फार्मासिस्ट, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ) को कोविड-19 प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग-

1. राज्य स्तरीय आरोग्य कोविड सेल द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव एवं पुनर्वास संबंधी गाइडलाइन तैयार कर जिलास्तर के आरोग्य कोविड सेल के माध्यम से सभी फील्डकर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करायी जाएगी।
2. ट्रेनिंग के उपरान्त सभी आरोग्य केन्द्रों के चिकित्साकर्मियों को प्रतिदिन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन माध्यम से जिला आरोग्य कोविड सेल को उपलब्ध कराएगा। जिला कोविड सेल प्राप्त जानकारी को उसी दिवस राज्य आरोग्य कोविड सेल को उपलब्ध कराएगा। राज्य कोविड सेल समस्त जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित कर शासन व महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अवगत कराएगा।

प्रचार/प्रसार-

निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड आरोग्य केन्द्रों, कोविड-19 से बचाव हेतु औषधियों, आहार-विहार, दिनचर्या एवं कॉमन योग प्रोटोकॉल की जानकारी creatives (flyers, brochures, booklets, short video इत्यादि) तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-18(म०)/XXVII(3)/2020, दिनांक 12 मई, 2020 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

दिलीप जावलकर,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

18 मई, 2020 ई०

संख्या 258/XXVIII-2-2020-90/2008--श्री शशिभूषण बडोनी, प्रभारी अधिकारी (फार्मसी), वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600/- को नियमित चयनोपरान्त विशेष कार्याधिकारी (फार्मसी) वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600/- पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री बडोनी को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 जून, 2020 ई०

संख्या 369/XXXI(4)/20/-03(विविध)/2015-उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, अनु सचिव (लेखा) को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 78,800-2,09,200 पे-मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नत अधिकारी को उप सचिव (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- श्री नरेन्द्र सिंह उप सचिव लेखा अनुभाग-01, 03, 09 एवं 11 का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-04 को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ०प्र० सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तत्काल में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्काल में निष्कारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,

सचिव।

गृह अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 193/XX(1)-2020-3(7)2006-उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-1 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12, ग्रेड वेतन- ₹ 7600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती ममता बोहरा
2.	श्रीमती सरिता डोवाल

2-पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परीवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है।

3-उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 194/XX(1)-2020-3(7)2006-उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, ग्रेड वेतन- ₹ 6600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी सर्वश्री
1.	लोकजीत सिंह
2.	चन्द्रमोहन सिंह

2. पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परीवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है।

3. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 195/XX(1)-2020-3(7)2006—उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, ग्रेड वेतन—₹ 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी सर्वश्री
1.	शेखर चन्द्र सुयाल
2.	कमला बिष्ट
3.	वीरेन्द्र प्रसाद डबराल
4.	अभय कुमार सिंह
5.	प्रकाश चन्द्र देवली
6.	मनोज कुमार ठाकुर
7.	बीर सिंह
8.	राकेश चन्द्र देवली
9.	विजेन्द्र दत्त डोभाल
10.	चक्रधर अन्धवाल
11.	पंकज गैरोला
12.	वीरेन्द्र सिंह रावत
13.	महेश चन्द्र बिन्जोला
14.	रायमन सिंह नवियाल
15.	धन सिंह तोमर
16.	विजय थापा

2- उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा आयोग खण्डपीठ, देहरादून में बोजित निर्देश याचिका संख्या 140/डीबी/2019 प्रकाश चन्द्र देवली बनाम राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्या 123/डीबी/2019 राकेश चन्द्र देवली बनाम राज्य व अन्य एवं निर्देश याचिका संख्या 139/डीबी/2019 विजेन्द्र दत्त डोभाल बनाम राज्य व अन्य में पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

3- पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है।

4- उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ज्योतिर्मय त्रिपाठी,
अनु सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

12 मई, 2020 ई०

संख्या 389/XXXI(1)/2020-पदो०-03/2017-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान ₹ 66,100-1,77,500) के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 28 मार्च, 2018 से नौशनल रूप से पदोन्नत करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

4. उक्त प्रोन्नति मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या: 70 डी०बी० ललित मोहन आर्य एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

12 मई, 2020 ई०

संख्या 390/XXXI(1)/2020-पदो०-03/2017-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन-लेवल 10 (वेतनमान ₹ 66,100-1,77,500) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) श्री प्रदीप डिमरी
- (2) श्री जनार्दन प्रसाद नौटियाल
- (3) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय
- (4) श्री भगवान सिंह
- (5) श्री सुनील कुमार लखेड़ा
- (6) श्री सन्तोष उग्रेती
- (7) श्री राकेश धर द्विवेदी
- (8) श्री मनोज कुमार सिंह
- (9) श्री पुष्पेन्द्र सिंह पंवार
- (10) श्री मयंक सिंह बिष्ट
- (11) श्री राजीव नयन पाण्डेय
- (12) श्री नागेन्द्र सिंह मट्टूड़ा
- (13) श्री राजीव

- (14) श्री अशोक पाण्डेय
- (15) श्री धर्मेन्द्र सिंह
- (16) श्रीमती राखी भटनागर
- (17) डॉ० अशोक कुमार मिश्र
- (18) श्री सुनील गुप्ता
- (19) श्रीमती प्रमिला कोठारी

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा० लोक सेवा आयोग, देहरादून में योजित निर्देश याचिका: 70/डी०बी०/2018 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4. अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

आज्ञा से,
भूपाल सिंह मनराल
सचिव (प्रभारी)।

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

13 मई, 2020 ई०

संख्या 214/XVIII(3)/2020-3(17)/2016-राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 676/XVIII(3)/2016-03(17)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएँ इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	हल्द्वानी	भावरछः खाता	जवाहर ज्योति दमुवाढ़ंगा

आज्ञा से,
सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 214/XVIII(3)/2020-3(17)/2016, dated May 13, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 13, 2020

No. 214/XVIII(3)/2020-3(17)/2016—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 676/XVIII(3)/2016-03(17)/2016, dated 30 December, 2016 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Haldwani	Bhabar Che: Khanta	Jawahar Jyoti Damuwadhunga

By Order,

SUSHIL KUMAR,
Secretary in-charge.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1942 शक सम्बत)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आझाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

23 मई, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिशनर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 240/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि-अनुभाग/2020-21/देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याए 325/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-1; 326/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-8; 327/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-9; 328/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-11; 329/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-12; 330/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-13; 331/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-14; 332/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-16; 333/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-17; 334/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-18; 335/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-19; 336/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-27; 337/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-02; 338/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-03; 339/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-30; 340/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-31; 341/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-32; 342/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-33; 343/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-34 एवं 344/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-35 समदिनांकित 20 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की अधिसूचना संख्या 514/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अधीन आने वाली विदेशी विमानन कम्पनियों हेतु धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होने; निगमित दिवालिया सम्बन्धी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों हेतु विशेष प्रक्रिया जारी किए जाने; अधिसूचना संख्या 430/2019 दिनांक 31 मई, 2019 में संशोधन; ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है, तथा नियम 54 के उपनियम (2)(3)(4) तथा (4क) में विनिर्दिष्ट है, को एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने; यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो नियम 54 के उपनियम (2)(3)(4) तथा (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और IGST Act, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 जारी किए जाने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 की उपधारा 6(ख) या उपधारा 8(ग) के उपबन्ध व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होने; किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण हेतु आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाए जाने; अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाए जाने; त्रैमास अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तथा जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्योरे प्रस्तुत करने हेतु तिथि निर्धारित किए जाने; शासन की अधिसूचना संख्या 525/2017 तथा 514/217 समदिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन करने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020 जारी किए जाने; शासन की अधिसूचना संख्या 524/2017 दिनांक 29 जून, 2017 अधिसूचना संख्या 87/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2019, अधिसूचना संख्या 116/2018 दिनांक 31 जनवरी, 2018 अधिसूचना संख्या 430/2019 दिनांक 31 मई, 2019 में संशोधन करने तथा महामारी कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यवाही को पूरा करने या उसके अनुपालन की समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां करारकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई0

संख्या 325/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-1-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेतर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची II-6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 242 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची IV-14 प्रतिशत में, क्रम संख्या 228 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

" 228	कोई भी अध्याय	लॉटरी"
-------	---------------	--------

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 325/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-1, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 325/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-1—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely—

In the said notification,—

(a) in Schedule II-6 Percent, S.No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule IV-14 Percent, for S.No. 228 and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely:—

"228.	Any chapter	Lottery".
-------	-------------	-----------

2. This notification shall deemed to have come into force from the 1st day of March, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई0

संख्या 326/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-8-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये दिनांक 01 मार्च, 2020 से प्रवृत्त जायेंगे।
- नियम 31क में संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क में स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ-1 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>(2) (क) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी की पूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100/112 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत, जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;</p> <p>(ख) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पूर्ति का मूल्य, अंकित मूल्य का 100/128 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;</p> <p>स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां -</p> <p>(क) "राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी" से ऐसी लाटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी;</p> <p>(ख) "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी" से ऐसी लाटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है; और</p> <p>(ग) "आयोजित करने वाले राज्य" का वही अर्थ होगा जो उसे लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में दिया गया है।</p>	<p>"(2) लाटरी की पूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100/128 या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जायेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण :- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।</p>

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 326/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-8, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 326/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-8—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall be deemed to have come into force from 01st day of March, 2020

Amendment in rule 31A In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 31A, for sub-rule (2) set out in column-1, the sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:—

column-1 Existing sub-rule	column-1 Hereby substituted sub-rule
<p>(2) (a) The value of supply of lottery run by State Government shall be deemed to be 100/112 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.</p> <p>(b) The value of supply of lottery authorised by State Government shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.</p> <p><i>Explanation:—</i> For the purposes of this sub-rule, the expressions—</p> <p>(a) “lottery run by State Government” means a lottery not allowed to be sold in any State other than the organizing State;</p>	<p>“(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.</p> <p><i>Explanation:—</i> For the purposes of this sub-rule, the expression “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010”.</p>

<p>(b) "lottery authorised by State Government" means a lottery which is authorised to be sold in State(s) other than the organising State also; and</p> <p>(c) Organising State has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.</p>	
--	--

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 327 / 2020 / 5(120) / XXVII(8) / 2020 / CT-9-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिर्नियम संख्या 08 वर्ष 2017) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, व्यक्तियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी है, जो कि विमानन कंपनी है और जिनके द्वारा कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के उप नियम (2) का अनुपालन किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त व्यक्तियों को, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, किसी वित्तीय वर्ष हेतु, भारतीय कारबार के बाबत प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 327/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-9, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 327/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-9—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C to the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 328/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-11—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक नीचे यथाउल्लिखित निम्न विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. **रजिस्ट्रीकरण.** ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड था, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आईआरपी/ आरपी इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा, जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

3. **विवरणी.-** ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40 के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4. **इनपुट का प्रत्यय.-** (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजकों पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के शर्तों के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन पर जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की शर्तों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा नकद खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं।

6. यह अधिसूचना 21 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 328/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-11, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 328/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-11—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. Registration.— The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. Return.— The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.

4. **Input tax credit.**-(1) The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

(2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.

5. Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

6. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 21st day of March, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 329/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-12—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या 430/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-21 दिनांक 31 मई, 2019 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, वर्तमान परन्तुकों के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु उक्त व्यक्तियों, जिनके द्वारा प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अवधियों के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दी गयी है, ऐसे करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अवधियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 329/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-12, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 329/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-12- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 430/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-21 dated 31st May, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, after the existing provisos, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 have furnished a return in FORM GSTR-3B under the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such taxpayers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 for all the tax periods in the financial year 2019-20."

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 330/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-13—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या 63/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-70 दिनांक 17 जनवरी, 2020 (दिनांक 21 मार्च, 2020 को अधिक्रमिण समझा जायें) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 330/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-13, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 330/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-13—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred as said rules), the Governor, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Uttarakhand, No. 63/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-76 dated 17th January, 2020 (deemed to be superseded on 21st March, 2020), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is pleased to allow to notify registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall deemed to have come into force from the 1st October, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 331/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-14—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर और उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 65/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-72 दिनांक 17 जनवरी, 2020 (दिनांक 21 मार्च, 2020 को अधिक्रमित समझा जाय) को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (व्यू आर) कोड होगा।

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्राप्त को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (व्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 331/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-14, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 331/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-14—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, **THEREFORE**, In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Uttarakhand, No. 65/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-72 dated 17th January, 2020 (deemed to be superseded on 21st March, 2020), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is pleased to allow to notify that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall deemed to have come into force from the 1st day of October, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई0

संख्या 332/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-16-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रभावी समझे जायेंगे।
- नियम 8 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।”
- नियम 9 में संशोधन 3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से, नियम 9 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”
- नियम 25 में संशोधन 4. उक्त नियमों के नियम 25 में, स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-1 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन - जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी - 30 में समान पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।	“कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन- जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”

नियम 43 में
संशोधन

5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से,-

(क) स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-1 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
<p>(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा ;</p> <p>परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;</p> <p>स्पष्टीकरण : खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है ।</p>	<p>"(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा ;</p> <p>परंतु जहां खंड (क) के अधीन पूर्व में आच्छादित कोई पूंजी माल, इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आच्छादित है, ऐसे पूंजी मालों के संबंध में प्रत्यय कर "क" के रूप में दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में इस शर्त के अधीन जमा किया जायेगा कि ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसे पूंजी माल खंड (क) से आच्छादित थे, 'टाई' के रूप में दर्शाए गये अपात्र प्रत्यय को प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गम कर दायित्व में सम्मिलित किया जायेगा;</p> <p>परंतु यह कि रकम 'टाई' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर - 3 ख में घोषित की जाएगी ;</p> <p>स्पष्टीकरण: प्राप्ति पर खंड (क) के अंतर्गत घोषित पूंजी माल के सम्बन्ध में धारा 18 की उपधारा (4) के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे यदि यह इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आच्छादित है।"</p>

(ख) स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-1 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
<p>(घ) 'टी' के रूप में द्योतक खंड (ग) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकम किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगी ;</p> <p>परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को 'टी' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ;</p>	<p>(घ) समान पूंजी माल जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है जो कि "टी सी" के रूप में निरूपित किया जाता है, के संबंध में खंड 'ग' के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा "क" की समेकित राशि, ऐसे पूंजी माल के संबंध में समान प्रत्यय होगा.</p> <p>परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है तथा वह खंड (ग) के अधीन पश्चात्तवर्ती भी आच्छादित है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 'टी सी' पर जोड़ा जाएगा ;"</p>

(ग) खंड (ड.) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण - संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा।”;

(घ) खंड (च) का लोप किया जाएगा।

नियम 80 में
संशोधन

6. उक्त नियमों में, नियम 80 में उपनियम (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा :-

“परन्तु कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका सकल कारोबार वि. तीव्य वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रूपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभि प्रमाणित हो, वि. तीव्य वर्ष 2018-19 के लिए FORM GSTR-9C में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा अधि सूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।”

नियम 86 में
संशोधन

7. उक्त नियमों के, नियम 86 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी दोषपूर्ण संदत्त कर या अधिव्य में संदत्त कर के रूप में संदत्त धनराशि के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा।”

नियम 89 में
संशोधन

8. उक्त नियमों के नियम 89 में, उपनियम (4) में, स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खंड (इ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(इ) माल के शून्य दर पूर्ति के आवर्त से ऐसे पूर्तियों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है ;	“(इ) मालों का शून्य-दर पूर्ति का व्यापारावर्त का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति का मूल्य या कीमत जो कि पूर्तिकार द्वारा यथाघोषित उसी पूर्तिकार या समान पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किये गये घरेलू मालों पूर्ति के कीमत का 1.5 गुना; इनमें से जो भी कम है, है, एवम इसमें उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए किये गये दावे से सम्बंधित पूर्तियों का व्यापारावर्त सम्मिलित नहीं है;”

नियम 92 में
संशोधन

9. उक्त नियमों के नियम 92 में, -

(क) उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवेदन के परीक्षण पर उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नकदी में, सुसंगत अवधि-

के लिए उन्मोचित कर-दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक, वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आरएफडी-06 में अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम तथा अतिशेष वापसी योग्य रकम उल्लिखित करते हुए एक आदेश करेगा और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में इनपुट कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जीएसटी पीएमटी -03 जारी करेगा।”;

(ख) उप-नियम (4) में, “उप-नियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात “या उप-नियम (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (5) में, “उप-नियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात “या उप-नियम (1क)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे”;

नियम 96 में
संशोधन

10. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के खंड (ख) जो कि 23 अक्टूबर, 2017 में प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ वहाँ पर उपभुक्त नहीं माना जायेगा जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट पर एकीकृत माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) की छूट का उपयोग किया गया है।”

नये नियम 96ख
का अन्तःस्थापन

11. उक्त नियमों में, नियम 96क के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“96ख. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या एकीकृत कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात आगम की प्राप्ति नहीं होती है-

(1) जहां मालों के निर्यात पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या मालों के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर की कोई वापसी किसी आवेदक को की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में पूर्णतः या अंशतः, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए भारत में, विक्रय आगम की प्राप्ति नहीं हुई है, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को विक्रय आगम की अप्राप्ति की सीमा तक उक्त अवधि के समाप्ति या यथास्थिति, विस्तारित अवधि के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, जमा करेगा, जिसमें असफल रहने पर प्रतिदाय की गयी रकम की वसूली अधिनियम की धारा 73 या धारा 74, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंधों के अनुसार धारा 50 के अधीन ब्याज सहित जैसा कि त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए लागू है, की जाएगी :

परंतु जहां ऐसे निर्यात मालों के संबंध में पूर्णतः या अंशतः, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर विक्रय आगम की प्राप्ति आवेदक द्वारा नहीं की गयी है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय आगम की प्राप्ति की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त प्रतिदाय की वसूली नहीं होगी ।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय की धनराशि उससे वसूल किये जाने के पश्चात आवेदक द्वारा पूर्णतः या अंशतः, विक्रय आगम की प्राप्ति की गयी है और आवेदक विक्रय आगम की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी प्राप्ति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो ऐसी वसूल की गई रकम विक्रय आगम की प्राप्ति की सीमा तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय आगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर प्राप्त की गयी हो।

नियम 141 में
संशोधन

12. उक्त नियम में, नियम 141 के उप-नियम (2) में "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "उचित अधिकारी" रखा जाएगा।

प्ररूप जीएसटी
आरएफडी-01 में
संशोधन

13. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में नियम 89(2) (छ) के अधीन घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

वचन बंध

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि जीएसटी नियम, 2017 की धारा 96 ख के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करूंगा।

हस्ताक्षर-

नाम

पदनाम /प्रास्थिति।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 332/2020/5(120)/XXVII(8)/2019/CT-16, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 332/2020/5(120)/XXVII(8)/2019/CT-16—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020

Short Title and
Commencement

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd March, 2020.

- Amendment in rule 8** 2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 “(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01.04.2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration.”
- Amendment in rule 9** 3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from 01.04.2020, the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 “Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases.”
- Amendment in rule 25** 4. In the said rules, for rule 25 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Hereby substituted rule
<p>25. Physical verification of business premises in certain cases.- Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.</p>	<p>25. Physical verification of business premises in certain cases.-Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.”</p>

Amendment in rule 43 5. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1st April, 2020,-

(a) for clause (c) set out in column-1, the following clause set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing clause	Column-1 Hereby substituted clause
<p>(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', shall be credited to the electronic credit ledger and the useful life of such goods shall be taken as five years from the date of the invoice for such goods:</p> <p>Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, the value of 'A' shall be arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and the amount 'A' shall be credited to the electronic credit ledger;</p> <p><i>Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause.</i></p>	<p>"(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:</p> <p>Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as 'T₁₀', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:</p> <p>Provided further that the amount 'T₁₀' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in FORM GSTR-3B.</p> <p><i>Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause."</i></p>

(b) for clause (d) set out in column-1, the following clause set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing clause	Column-1 Hereby substituted clause
<p>(d) the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c), to be denoted as 'T_c', shall be the common credit in respect of capital goods for a tax period:</p> <p>Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) is subsequently covered under clause (c), the value of 'A' arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof shall be added to the aggregate value 'T_c';</p>	<p>"(d) the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T_c', shall be the common credit in respect of such capital goods:</p> <p>Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value 'T_c';"</p>

(c) in clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods."

(d) clause (f) shall be omitted.

Amendment in rule 80 6. In the said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C** for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

Amendment in rule 86 7. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03.**”

Amendment in rule 89 8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C) set out in column-1, the following clause set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing clause	Column-2 Hereby substituted clause
(C) Turnover of zero-rated supply of goods means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;	“(C) Turnover of zero-rated supply of goods” means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;”

Amendment in rule 92 9. “In the said rules, in rule 92-
(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM RFD-06** sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period,

mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.”;

(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (1A)”, shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, figures and letter “or sub-rule (1A)”, shall be inserted.

**Amendment in
rule 96**

10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10), in clause (b) with effect from the 23rd October, 2017, the following Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications.”

**Insertion of new
rule 96A**

11. In the said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, namely:-

“96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised. -

(1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, the extended

period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India."

Amendment in rule 141 12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word "Commissioner", the words "proper officer" shall be substituted.

Amendment in FORM GST RFD-01 13. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted, namely:-

"UNDERTAKING"

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

Signature-

Name -

Designation / Status".

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 333/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-17-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

- (क) व्यक्ति;
- (ख) सभी प्रकार के प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 333/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-17, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 333/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-17-WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, **THEREFORE**, In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:-

- (a) Individual;
- (b) authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 334/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-18—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिससे कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्ति को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 334/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-18, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 334/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-18—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 335/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-19—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिससे—

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 335/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-19, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 335/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-19—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

- (a) authorised signatory of all types;
- (b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
- (c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 336/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-27—चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि।
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितंबर 2020	31 अक्टूबर, 2020

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 336/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-27, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 336/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-27—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	April, 2020 to June, 2020	31 st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31 st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 337/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-02-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

- (1) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-

- (11) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "और (i)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 337/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-02, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 337/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-02-WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely,

(3)	(4)	(5)
"(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets, and figures "and (ia)" shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 338/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-03—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की अनुशंसा पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अप्रेतर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में,

क. अनुसूची I- 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II- 6 प्रतिशत में,

(i) क्रम संख्या 75 और इससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:

75"अ	3605 00 10	सभी माल;"
------	------------	-----------

(ii) क्रम संख्या 202 और 203 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची III- 9 प्रतिशत में,

(i) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 379 में, स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " सभी माल" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 338/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-03, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 338/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CTR-03—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (3) of section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5 Percent, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6 Percent, -

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

"75A.	3605 00 10	All goods";
-------	------------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9 Percent, -

(i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be substituted;

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 338/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-30-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 03 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।
- नियम 3 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।"
- नियम 36 में संशोधन 3. उक्त नियम के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु कि उक्त शर्तें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होंगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ब की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 339/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-30, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 339/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-30—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :—

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd day of April, 2020.

Amendment in rule 3 2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020.”

Amendment in rule 36 3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 340/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-31-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 524/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के प्रथम प्रस्तर में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र०सं०	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 340/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-31, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 340/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-31--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in notification of the Government of Uttarakhand, No. 524/2017/9 (120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:-"

Table

S. No.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020 April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of June, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020 March, 2020 April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 341/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-32—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 97/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CT-76 दिनांक 24 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

“परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलम्ब फीस उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है,

तालिका

क्र०सं० (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।”

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 341/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-32, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 341/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-32—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 97/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CT-76 dated 24th January, 2019, namely:—

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

Table

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of June, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 342/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-33-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 दिनांक 31 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 342/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-33, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 342/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-33—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 dated 31st January, 2018, as amended from time to time, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in FORM GSTR-1 by the due date, but furnishes the said details in FORM GSTR-1, on or before the 30th day of June, 2020.”

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई०

संख्या 343/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-34—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 430/2019/3(120)/XXVI(8)/2019/CT-21 दिनांक 31 मई, 2019 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) दूसरे प्रस्तर में वर्तमान परन्तुकों के पश्चात निम्न परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”;

(ii) तीसरे प्रस्तर में निम्न परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 343/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-34, dated May 20, 2020 for general information.

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 343/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-34--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 430/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-21 dated 31st May, 2019, namely:-

In the said notification,-

(i) in the second paragraph, after the existing provisos the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

अधिसूचना

20 मई, 2020 ई0

संख्या 344 / 2020 / 5(120) / XXVII(8) / 2020 / CT-35—चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के दृष्टिगत परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि -

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी -

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण, किसी भी नाम से हो, द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, बयान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जिस भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है -

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, परंतु उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ङ) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) पर वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियम;

(ii) जहां उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान

समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।

2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से प्रवृत्त समझा जाएगा।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 344/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-35, dated May 20, 2020 for general information:

NOTIFICATION

May 20, 2020

No. 344/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-35—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify, as under,-

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of:-

- (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
- (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -

- (a) Chapter IV;
 - (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
 - (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
 - (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
 - (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;
- (ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त (वि०वे०) राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।